

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 149

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

कर राजस्व की हानि पर आईबीसी कार्यसंरचना का प्रभाव

149. सुश्री इकरा चौधरी:

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कर राजस्व की हानि पर वर्तमान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यसंरचना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया है;
- (ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आईबीसी की धारा 53 के तहत, उपभोक्ताओं से एकत्र किए गए अप्रत्यक्ष करों सहित सरकारी बकाया राशि को दिवाला प्रक्रियाओं के दौरान बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है;
- (ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उपभोक्ताओं द्वारा व्यवसायों को दिए जाने वाले उक्त अप्रत्यक्ष करों को आवश्यक रूप से भारत की समेकित निधि का हिस्सा बनाया जाना चाहिए;
- (घ) क्या सरकार आईबीसी में किसी संशोधन पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले करों को उच्च प्राथमिकता दी जाए; और
- (ङ) क्या सरकार आईबीसी कानून के तहत दी गई कर छूट के कारण छोड़े गए कुल कर राजस्व की राशि और उक्त कानून में अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के बारे में आंकड़े एकत्र करती है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सरकार द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 53 के अनुसार, सरकारी बकाया राशि को सुरक्षित लेनदारों, कामगारों, कर्मचारियों और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों से संबंधित बकाया राशि से नीचे रखा गया है।

(घ): अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ): सरकार द्वारा ऐसा कोई डाटा एकत्र/रखरखाव नहीं किया जाता है क्योंकि आईबीसी कानून के तहत कर छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
